

[2023] 2 एस. सी. आर. 582

/

[2023] 2 एस सी आर।

द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ओआरएस. v.

/

चंदरवीर सिंह नेगी

(सिविल अपील संख्या 2023 की 1276-1277) 24 फरवरी, 2023

/

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:s.100-सीमा अधिनियम, 1973-कला।58, 72 - दूसरी अपील-विधि के सारवान प्रश्न को तैयार करना-सीमा द्वारा रोक-प्रत्यर्थी द्वारा घोषणा के लिए मुकदमा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए अपीलकर्ताओं को निर्देश देने की मांग-प्रत्यर्थी का मामला कि प्रत्यर्थी की भूमि पर सड़क का निर्माण किया गया था, कोई मुआवजा नहीं दिया गया था और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था-निचली अदालत ने मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर दिया-पहली अपीलीय अदालत द्वारा स्थगित-प्रत्यर्थी द्वारा दूसरी अपील-उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात -अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:प्रत्यर्थी की भूमि पर प्रश्न सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था; वर्ष 1987 में यदि कोई पेड़ क्षतिग्रस्त/हटाया गया था; संरक्षण दीवार का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था और वर्ष 2003 में दायर किया गया था-उक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जब निचली विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था और जब इसे पहली अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, तो उच्च न्यायालय को यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों के उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।100 - उच्च न्यायालय ने सीमा और/या मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने पर विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनाया-उच्च न्यायालय सामान्य और व्यापक सिद्धांतों पर चला गया है-उच्च न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

/

/

/

/

सिविल अपील की अधिकारिता 2023 की सिविल अपील Nos.1276-1277।

/

2018 के आर. पी. संख्या 8 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 09.08.2019 के निर्णय और आदेश से और 2007 के आर. एस. ए. No.270 में दिनांकित 22.08.2016 से।

अभिमन्यु झांबा, सुश्री थोंपिनाव थंगल, समीर अली खान, सुश्री हटनीमावी, शिवम पराशर, निखिल जगोत्रा, सुश्री ऋचा भारती, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

582

583

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम चंदरवीर सिंह नेगी ए

/

सुश्री राधिका गौतम, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. शिमला में हिमाचल प्रदेश के उच्च विचारण न्यायालय द्वारा 2007 की नियमित दूसरी अपील संख्या 270 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च विचारण न्यायालय ने उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को खारिज कर दिया है, जिसमें मुकदमे को खारिज कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप मुकदमे में याचिकाकर्ता को वादी की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि शिकायत में उल्लेख किया गया है और साथ ही साथ अपीलकर्ता द्वारा यहां प्रस्तुत समीक्षा आवेदन को खारिज करने के आदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. कि इसमें प्रतिवादी-मूल वादी ने वादी की भूमि के संबंध में अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने और उसे पूरा करने और उसके फलदार पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां मूल प्रतिवादियों की घोषणा, अनिवार्य कार्रवाई और अपीलकर्ताओं को निर्देश देने के लिए विद्वत विचारण

विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया।वादी के अनुसार यहाँ अपीलार्थी मूल प्रतिवादी एन. ओ. एस. हैं। 1, 2 और 3 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना, वादी की भूमि पर "टिकरी-लरोट-बोदरा कवार रोड" के रूप में जानी जाने वाली सड़क का निर्माण किया, लेकिन वादी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया।फलों वाले पौधों को भी नुकसान पहुंचा है।

/

/

2.1 इसमें अपीलकर्ताओं-मूल प्रतिवादियों ने मुकदमे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मुकदमा सीमा विधि द्वारा वर्जित है; कि वादी विभाग में साथी के रूप में काम कर रहा था और वास्तव में सड़क का निर्माण उसके अनुरोध पर और सहमति के अनुसार किया गया था; वादी ने मुआवजे के अपने दावे को माफ कर दिया क्योंकि सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में उसकी सहमति से किया गया था।विद्वत् विचारण विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को विरचित किया:

/

“मुद्दा नं.एल:- क्या वादी घोषणा की राहत का हकदार है, जैसा कि प्रार्थना की गई है?ओपीपी

/

मुद्दा नं.2:- क्या वादी आरोप के अनुसार मुआवजे का हकदार है?ओपीपी

मुद्दा नं. 3:- क्या सूट रखरखाव योग्य नहीं है?ओ. पी. डी. इश्यू नं. 4:- क्या मुकदमा समय की पाबंदी है?ओपीडी

/

584

/

[2023] 2 एस सी आर।

मुद्दा नं. 5:- क्या वादी अपने कृत्यों और आचरण से विचलित है?ओपीडी

मुद्दा संख्या 6:-क्या न्यायालय ी शुल्क और अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य से मुकदमे का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है?ओपीडी

अंक संख्या 7:-क्या वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है?ओपीडी

/

मुद्दा संख्या 8:-क्या मुकदमा आवश्यक पक्षों के गैर-जॉइंडर के लिए बुरा है?ओपीडी

मुद्दा संख्या 9:- राहत "।

/

2.2 अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की सराहना करने और इस तथ्य पर विचार करने पर कि सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था और 2002 तक वादी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी और वर्ष 1987 में कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के कारण, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने मुद्दा संख्या 4 को प्रतिवादियों के पक्ष में ठहराया और कहा कि मुकदमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 और 72 को ध्यान में रखते हुए सीमा द्वारा वर्जित था। विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने वादी के खिलाफ Nos.3,5 और 7 का मुद्दा भी रखा। नतीजतन, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने मुकदमे को खारिज कर दिया। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा वाद को खारिज करते हुए पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल वादी द्वारा पसंद की गई दूसरी अपील को अनुज्ञात कर लिया है। उच्च न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न विरचित किए:

/

/

“क्या निम्नलिखित न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष या निर्णय और डिक्री पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ने, रिकॉर्ड पर साक्ष्य और सामग्री की गलत व्याख्या और तय स्थिति या कानून के खिलाफ है? ”

/

वादी के पक्ष में विधि के उपरोक्त प्रश्न को रखते हुए उच्च न्यायालय ने सीमा के संबंध में मुद्दे पर विचार किए बिना दूसरी अपील की अनुज्ञात है और नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप मुकदमे का फैसला सुनाया है।

/

2.3 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को अनुमति देने और ए दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों अपास्त करते हुए करने और खारिज करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।

/

585

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम चंदरवीर सिंह नेगी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

दोनों न्यायालयों द्वारा जिनके नीचे इस प्रकार अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर थे।

2.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि इस तरह की सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था और वह भी वादी की मदद और सहमति से और 2002 तक किसी भी समय, उसने मुआवजे का भुगतान न प्रश्न के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बयान में वादी सहित वादी गवाहों ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि प्रश्न सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2002 में पहली बार वादी ने मुख्यमंत्री को एक अभ्यावेदन में मुआवजे का भुगतान न करने के संबंध में शिकायत की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जब नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना करते हुए कहा कि मुकदमा सीमितता से वर्जित था, तो उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की है।

/

/

/

2.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और मुकदमे को खारिज करने वाले विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाए।

3. हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखा है। हमने वादी गवाहों के बयान पर भी विचार किया है जिन पर विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया था। वादी गवाहों के बयान से यह देखा जा सकता है कि वादी और अन्य गवाहों ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि वादी की भूमि पर प्रश्न भूमि का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था। वादी गवाहों ने यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 1987 में वादी की भूमि पर संरक्षण दीवार का निर्माण किया गया था। यहां तक कि वादी और उसके गवाहों के अनुसार वर्ष 1987 में फलों के पेड़ क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गए थे। यहां तक कि मुकदमे में की गई कार्रवाई का कारण वर्ष 1987 में सड़क का निर्माण था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 और 72 पर विचार करते हुए सीमा द्वारा वर्जित था और जब प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, तो उच्च न्यायालय को सी. पी. सी. की धारा 100 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों के उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

/

/

/

/

586

/

[2023] 2 एस सी आर।

3.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह प्रतिवादियों की ओर से विशिष्ट मामला था कि सड़क का निर्माण वादी की मदद और सहमति से किया गया था जो मुख्य रूप से 2002 तक कोई विवाद नहीं उठाने वाले वादी के आचरण से स्थापित और साबित होता है।

3.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और बनाए गए विधि के सारगर्भित प्रश्न से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने सीमा और/या मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने पर विधि का कोई सारगर्भित प्रश्न नहीं विरचित है। उच्च न्यायालय सामान्य और व्यापक सिद्धांतों पर चला है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उन वास्तविक तथ्यों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है जो यहाँ ऊपर वर्णित हैं। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहा जा सकता है। चाहे यह तथ्य बना रहे कि प्रश्न सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था; पेड़, यदि कोई हों, तो वर्ष 1987 में क्षतिग्रस्त/हटाए गए थे; वर्ष 1987 में वादी की भूमि पर प्रतिधारण/सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया था और मुकदमा वर्ष 2003 में दायर किया गया था और इसलिए सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 और 72 को देखते हुए मुकदमे को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अलग करने का अधिकार है।

/

/

/

4. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त और निरस्त किया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद को खारिज करने की पुष्टि करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।

/

तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुज्ञात जाती है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

निधि जैन

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायक: अभिषेक अग्रिहोत्री और तमन्ना, एलसीआरए)

/

/